भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया गया

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना

6. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:
श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार एक डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे देश में लोगों को डिजिटल बैंकिंग, द्वार पर बैंकिंग सेवाएं तथा डिजिटल उधार प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): सरकार ने डिजिटल बैंकिंग, डोर स्टेप सेवाएं तथा डिजिटल उधार प्लेटफार्म उपलब्ध कराने को सुकर बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) एमएसएमई ऋणों के लिए ऑनलाइन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु क्रेडिट ब्यूरो, आयकर तथा माल और सेवाकर (जीएसटी) आंकड़ों का एक साथ उपयोग करते हुए *PSBloansin59minutes.com* के माध्यम से डिजिटल उधार को स्पर्शरहित बनाने की शुरुआत की गई है।

(2) ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के ऑनबोर्डिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी आधार पर एमएसएमई के लिए ऑनलाइन बिल भुनाई को सक्षम बनाया गया है तथा ऑनलाइन भुनाए गए बिलों के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है।

(3) पेंशनभोगियों के लिए सरकार की 'जीवन प्रमाण' पहल ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अद्यतित करने की सुविधा प्रदान की है।

(4) सरकार द्वारा शुरु किए गए पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत,-

(i) दी जाने वाली सेवाओं (43), ग्राहक हितैषी सुविधाओं (137) तथा क्षेत्रीय भाषा ग्राहक इंटरफेस (8) की औसत संख्या में वृद्धि के माध्यम से मोबाइल तथा इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंच को बेहतर बनाया गया है।

(ii) अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋणों (पांच पीएसबी में), सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों (पांच पीएसबी में "शिशु मुद्रा") तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को ऋणों के नवीनीकरण (तीन पीएसबी में) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों में आद्योपांत स्वचालित डिजिटल उधार की शुरुआत की गई है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 में आरंभ किए गए ऋण संबंधी आवेदन में से 40,819 करोड़ रुपए के खुदरा संवितरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सात बड़े बैंकों में डिजिटल चैनल के माध्यम से डिजिटल खुदरा ऋण आवेदन की शुरुआत की गई है।

(iv) ग्राहक आवश्यकता चालित, विश्लेषण आधारित ऋण प्रस्ताव पर जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के सात बड़े बैंकों द्वारा 49,777 करोड़ रुपए की राशि के नए खुदरा ऋणों का संवितरण किया गया है।

इसके फलस्वरूप पीएसबी के कुल वित्तीय लेनदेन में से 72% लेनदेन अब डिजिटल चैनल के माध्यम से किए जाते हैं और इसके साथ-साथ डिजिटल चैनल पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3.4 करोड़ से दोगुनी बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.6 करोड़ हो गई है तथा शाखा और मोबाइल चैनल के माध्यम से किए गए वित्तीय लेनदेन का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 29% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 76% हो गया है।

(5) पीएसबी के अलायन्स जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और भारतीय बैंक संघ की पहल है, ने कॉल सेन्टर (1800-121-3721 और 18000-103-7188), वेब पोर्टल (https://psbdsb.in/ और https://doorstepbanks.com/), मोबाईल एप (Google Play Store) के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरूआत की है। वर्तमान में देश के 100 शहरों में 13 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें नकदी आहरण अथवा जमा करना, चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-ऑर्डर आदि लाना, चेक-बुक मांग पर्ची लाना, आयकर फार्म सं. 15जी/15एच लाना, आयकर/जीएसटी चालान लाना और स्रोत (टीडीएस) पर टैक्स कटौती और आयकर उद्देश्यों के लिए फार्म-16 प्रमाण-पत्रों की डिलिवरी करना शामिल है।

सरकार के पास डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना निगम (डीबीआईसी) को स्थापित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऋण प्रस्ताव के लिए उपभोक्ताओं तथा कारोबार तक बेहतर पहुंच बनाने के उद्देश्य से बैंकों की संयुक्त पहल के रूप में साझा डिजिटल अवसंरचना प्लेटफार्म तैयार करने हेतु एक निगम की स्थापना के संबंध में कतिपय बैंकों ने विचार-विमर्श किया है।

*****